



::आयुक्त (अपील्स) का कार्यालय, वस्तु एवं सेवा कर और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क::
O/O THE COMMISSIONER (APPEALS), GST & CENTRAL EXCISE,

द्वितीय तल, जी एस टी भवन / 2nd Floor, GST Bhavan.

रेस कोर्स रिंग रोड, / Race Course Ring Road,

राजकोट / Rajkot - 360 001

Tele Fax No. 0281 - 2477952/2441142 Email: cexappealsrajkot@gmail.com



सत्यमेव जयते

रजिस्टर्ड डाक ए. डी. द्वारा :-

क	अपील / फाइल संख्या / Appeal / File No.	मूल आदेश सं / O.I.O. No.	दिनांक / Date
	V2/273,/RAJ/2017	67/ST/2016	30.03.2017

ख अपील आदेश संख्या (Order-In-Appeal No.):

RAJ-EXCUS-000-APP-071-2018-19

आदेश का दिनांक / Date of Order:	03.05.2018	जारी करने की तारीख / Date of issue:	04.05.2018
------------------------------------	-------------------	--	-------------------

**कुमार संतोष, आयुक्त (अपील्स), राजकोट द्वारा पारित /
Passed by Shri Kumar Santosh, Commissioner (Appeals), Rajkot**

ग अपर आयुक्त/ संयुक्त आयुक्त/ उपायुक्त/ सहायक आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/ सेवाकर, राजकोट / जामनगर / गांधीधाम। द्वारा उपरलिखित जारी मूल आदेश से सृजित: /
Arising out of above mentioned OIO issued by Additional/Joint/Deputy/Assistant Commissioner, Central Excise / Service Tax, Rajkot / Jamnagar / Gandhidham :

घ **अपीलकर्ता & प्रतिवादी का नाम एवं पता /Name&Address of the Appellants & Respondent :-**
1. M/s. Rayvains Infra P. Ltd., Office No. 24, 4th Floor Samrudhi Bhavan,, Gondal Road, Rajkot,

इस आदेश(अपील) से व्यथित कोई व्यक्ति निम्नलिखित तरीके में उपयुक्त प्राधिकारी / प्राधिकरण के समक्ष अपील दायर कर सकता है।/
Any person aggrieved by this Order-in-Appeal may file an appeal to the appropriate authority in the following way.

(A) सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रति अपील, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35B के अंतर्गत एवं वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 86 के अंतर्गत निम्नलिखित जगह की जा सकती है। /

Appeal to Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal under Section 35B of CEA, 1944 / Under Section 86 of the Finance Act, 1994 an appeal lies to:-

(i) वर्गीकरण मूल्यांकन से सम्बन्धित सभी मामले सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण की विशेष पीठ, वेस्ट ब्लॉक नं 2, आर. के. पुरम, नई दिल्ली, को की जानी चाहिए। /

The special bench of Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal of West Block No. 2, R.K. Puram, New Delhi in: all matters relating to classification and valuation.

(ii) उपरोक्त परिच्छेद 1(a) में बताए गए अपीलों के अलावा शेष सभी अपीलों सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (सिस्टेट) की पश्चिम क्षेत्रीय पीठिका, द्वितीय तल, बहुमाली भवन असारवा अहमदाबाद- 380016 को की जानी चाहिए। /

To the West regional bench of Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT) at, 2nd Floor, Bhaumali Bhawan, Asarwa Ahmedabad-380016 in case of appeals other than as mentioned in para- 1(a) above

(iii) अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करने के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (अपील) नियमावली, 2001, के नियम 6 के अंतर्गत निर्धारित किए गये प्रपत्र EA-3 को चार प्रतियों में दर्ज किया जाना चाहिए। इनमें से कम से कम एक प्रति के साथ, जहां उत्पाद शुल्क की मांग, ब्याज की मांग और लगाया गया जुर्माना, रुपए 5 लाख या उससे कम, 5 लाख रुपए या 50 लाख रुपए तक अथवा 50 लाख रुपए से अधिक है तो क्रमशः 1,000/- रुपये, 5,000/- रुपये अथवा 10,000/- रुपये का निर्धारित जमा शुल्क की प्रति संलग्न करें। निर्धारित शुल्क का भुगतान, संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा के सहायक रजिस्टार के नाम से किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा जारी रेखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया जाना चाहिए। संबंधित ड्राफ्ट का भुगतान, बैंक की उस शाखा में होना चाहिए जहां संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा स्थित है। स्थगन आदेश (स्टे ऑर्डर) के लिए आवेदन-पत्र के साथ 500/- रुपए का निर्धारित शुल्क जमा करना होगा। /

The appeal to the Appellate Tribunal shall be filed in quadruplicate in form EA-3 / as prescribed under Rule 6 of Central Excise (Appeal) Rules, 2001 and shall be accompanied against one which at least should be accompanied by a fee of Rs. 1,000/- Rs.5000/-, Rs.10,000/- where amount of duty demand/interest/penalty/refund is upto 5 Lac., 5 Lac to 50 Lac and above 50 Lac respectively in the form of crossed bank draft in favour of Asst. Registrar of branch of any nominated public sector bank of the place where the bench of any nominated public sector bank of the place where the bench of the T.ibunal is situated. Application made for grant of stay shall be accompanied by a fee of Rs. 500/-.

(B) अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील, वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 86(1) के अंतर्गत सेवाकर नियमावली, 1994, के नियम 9(1) के तहत निर्धारित प्रपत्र S.T.-5 में चार प्रतियों में की जा सकेगी एवं उसके साथ जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गयी हो, उसकी प्रति साथ में संलग्न करें (उनमें से एक प्रति प्रमाणित होनी चाहिए) और इनमें से कम से कम एक प्रति के साथ, जहां सेवाकर की मांग, ब्याज की मांग और लगाया गया जुर्माना, रुपए 5 लाख या उससे कम, 5 लाख रुपए या 50 लाख रुपए तक अथवा 50 लाख रुपए से अधिक है तो क्रमशः 1,000/- रुपये, 5,000/- रुपये अथवा 10,000/- रुपये का निर्धारित जमा शुल्क की प्रति संलग्न करें। निर्धारित शुल्क का भुगतान, संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा के सहायक रजिस्टार के नाम से किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा जारी रेखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया जाना चाहिए। संबंधित ड्राफ्ट का भुगतान, बैंक की उस शाखा में होना चाहिए जहां संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा स्थित है। स्थगन आदेश (स्टे ऑर्डर) के लिए आवेदन-पत्र के साथ 500/- रुपए का निर्धारित शुल्क जमा करना होगा। /

The appeal under sub section (1) of Section 86 of the Finance Act, 1994, to the Appellate Tribunal Shall be filed in quadruplicate in Form S.T.5 as prescribed under Rule 9(1) of the Service Tax Rules, 1994, and Shall be accompanied by a copy of the order appealed against (one of which shall be certified copy) and should be accompanied by a fees of Rs. 1000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied of Rs. 5 Lakhs or less, Rs.5000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied is more than five lakhs but not exceeding Rs. Fifty Lakhs, Rs.10,000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied is more than fifty Lakhs rupees, in the form of crossed bank draft in favour of the Assistant Registrar of the bench of nominated Public Sector Bank of the place where the bench of Tribunal is situated. / Application made for grant of stay shall be accompanied by a fee of Rs.500/-.

...2...

- (i) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 86 की उप-धाराओं (2) एवं (2A) के अंतर्गत दर्ज की गयी अपील, सेवाकर नियमवाली, 1994, के नियम 9(2) एवं 9(2A) के तहत निर्धारित प्रपत्र S.T.-7 में की जा सकेगी एवं उसके साथ आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अथवा आयुक्त (अपील), केन्द्रीय उत्पाद शुल्क द्वारा पारित आदेश की प्रतियाँ संलग्न करें (उनमें से एक प्रति प्रमाणित होनी चाहिए) और आयुक्त द्वारा सहायक आयुक्त अथवा उपायुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/ सेवाकर, को अपीलीय न्यायाधिकरण को आवेदन दर्ज करने का निर्देश देने वाले आदेश की प्रति भी साथ में संलग्न करनी होगी। / The appeal under sub section (2) and (2A) of the section 86 the Finance Act 1994, shall be filed in For ST.7 as prescribed under Rule 9 (2) & 9(2A) of the Service Tax Rules, 1994 and shall be accompanied by a copy of order of Commissioner Central Excise or Commissioner, Central Excise (Appeals) (one of which shall be a certified copy) and copy of the order passed by the Commissioner authorizing the Assistant Commissioner or Deputy Commissioner of Central Excise/ Service Tax to file the appeal before the Appellate Tribunal.
- (ii) सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय प्राधिकरण (सेस्टेट) के प्रति अपीलों के मामले में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 की धारा 35एफ के अंतर्गत, जो की वित्तीय अधिनियम, 1994 की धारा 83 के अंतर्गत सेवाकर को भी लागू की गई है, इस आदेश के प्रति अपीलीय प्राधिकरण में अपील करते समय उत्पाद शुल्क/सेवा कर मांग के 10 प्रतिशत (10%), जब मांग एवं जुर्माना विवादित है, या जुर्माना, जब केवल जुर्माना विवादित है, का भुगतान किया जाए, बशर्त कि इस धारा के अंतर्गत जमा कि जाने वाली अपेक्षित देय राशि दस करोड़ रुपए से अधिक न हो।
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर के अंतर्गत "मांग किए गए शुल्क" में निम्न शामिल है
(i) धारा 11 डी के अंतर्गत रकम
(ii) सेनवेट जमा की ती गई गलत राशि
(iii) सेनवेट जमा नियमावली के नियम 6 के अंतर्गत देय रकम
- बशर्त यह कि इस धारा के प्रावधान वित्तीय (सं. 2) अधिनियम 2014 के आरंभ से पूर्व किसी अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष विचाराधीन स्थगन अर्ज़ी एवं अपील को लागू नहीं होंगे।/
For an appeal to be filed before the CESTAT, under Section 35F of the Central Excise Act, 1944 which is also made applicable to Service Tax under Section 83 of the Finance Act, 1994, an appeal against this order shall lie before the Tribunal on payment of 10% of the duty demanded where duty or duty and penalty are in dispute, or penalty, where penalty alone is in dispute, provided the amount of pre-deposit payable would be subject to a ceiling of Rs. 10 Crores,
Under Central Excise and Service Tax, "Duty Demanded" shall include :
(i) amount determined under Section 11 D;
(ii) amount of erroneous Cenvat Credit taken;
(iii) amount payable under Rule 6 of the Cenvat Credit Rules
- provided further that the provisions of this Section shall not apply to the stay application and appeals pending before any appellate authority prior to the commencement of the Finance (No.2) Act, 2014.
- (C) **भारत सरकार को पुनरीक्षण आवेदन :**
Revision application to Government of India:
इस आदेश की पुनरीक्षण याचिका निम्नलिखित मामलों में, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1994 की धारा 35EE के प्रथम परंतुक के अंतर्गत अवर सचिव, भारत सरकार, पुनरीक्षण आवेदन इकाई, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, चौथी मंजिल, जीवन दीप भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001, को किया जाना चाहिए। /
A revision application lies to the Under Secretary, to the Government of India, Revision Application Unit, Ministry of Finance, Department of Revenue, 4th Floor, Jeevan Deep Building, Parliament Street, New Delhi-110001, under Section 35EE of the CEA 1944 in respect of the following case, governed by first proviso to sub-section (1) of Section-35B ibid:
- (i) यदि माल के किसी नुकसान के मामले में, जहां नुकसान किसी माल को किसी कारखाने से भंडार गृह के पारगमन के दौरान या किसी अन्य कारखाने या फिर किसी एक भंडार गृह से दूसरे भंडार गृह पारगमन के दौरान, या किसी भंडार गृह में या भंडारण में माल के प्रसंस्करण के दौरान, किसी कारखाने या किसी भंडार गृह में माल के नुकसान के मामले में। /
In case of any loss of goods, where the loss occurs in transit from a factory to a warehouse or to another factory or from one warehouse to another during the course of processing of the goods in a warehouse or in storage whether in a factory or in a warehouse
- (ii) भारत के बाहर किसी राष्ट्र या क्षेत्र को निर्यात कर रहे माल के विनिर्माण में प्रयुक्त कच्चे माल पर भरी गई केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के छुट (रिबेट) के मामले में, जो भारत के बाहर किसी राष्ट्र या क्षेत्र को निर्यात की गयी है। /
In case of rebate of duty of excise on goods exported to any country or territory outside India of on excisable material used in the manufacture of the goods which are exported to any country or territory outside India.
- (iii) यदि उत्पाद शुल्क का भुगतान किए बिना भारत के बाहर, नेपाल या भूटान को माल निर्यात किया गया है। /
In case of goods exported outside India export to Nepal or Bhutan, without payment of duty.
- (iv) सुनिश्चित उत्पाद के उत्पादन शुल्क के भुगतान के लिए जो ड्यूटी क्रेडिट इस अधिनियम एवं इसके विभिन्न प्रावधानों के तहत मान्य की गई है और ऐसे आदेश जो आयुक्त (अपील) के द्वारा वित्त अधिनियम (नं. 2), 1998 की धारा 109 के द्वारा नियत की गई तारीख अथवा समयावधि पर या बाद में पारित किए गए हैं। /
Credit of any duty allowed to be utilized towards payment of excise duty on final products under the provisions of this Act or the Rules made there under such order is passed by the Commissioner (Appeals) on or after, the date appointed under Sec. 109 of the Finance (No.2) Act, 1998.
- (v) उपरोक्त आवेदन की दो प्रतियां प्रपत्र संख्या EA-8 में, जो की केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (अपील) नियमावली, 2001, के नियम 9 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट है, इस आदेश के संप्रेषण के 3 माह के अंतर्गत की जानी चाहिए। उपरोक्त आवेदन के साथ मूल आदेश व अपील आदेश की दो प्रतियां संलग्न की जानी चाहिए। साथ ही केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35-EE के तहत निर्धारित शुल्क की अदायगी के साक्ष्य के तौर पर TR-6 की प्रति संलग्न की जानी चाहिए। /
The above application shall be made in duplicate in Form No. EA-8 as specified under Rule, 9 of Central Excise (Appeals) Rules, 2001 within 3 months from the date on which the order sought to be appealed against is communicated and shall be accompanied by two copies each of the OIO and Order-In-Appeal. It should also be accompanied by a copy of TR-6 Challan evidencing payment of prescribed fee as prescribed under Section 35-EE of CEA, 1944, under Major Head of Account.
- (vi) पुनरीक्षण आवेदन के साथ निम्नलिखित निर्धारित शुल्क की अदायगी की जानी चाहिए। /
जहाँ संलग्न रकम एक लाख रुपये या उससे कम हो तो रुपये 200/- का भुगतान किया जाए और यदि संलग्न रकम एक लाख रुपये से ज्यादा हो तो रुपये 1000 -/ का भुगतान किया जाए। /
The revision application shall be accompanied by a fee of Rs. 200/- where the amount involved in Rupees One Lac or less and Rs. 1000/- where the amount involved is more than Rupees One Lac.
- (D) यदि इस आदेश में कई मूल आदेशों का समावेश है तो प्रत्येक मूल आदेश के लिए शुल्क का भुगतान, उपर्युक्त ढंग से किया जाना चाहिये। इस तथ्य के होते हुए भी की लिखा पढ़ी कार्य से बचने के लिए यथास्थिति अपीलीय न्यायाधिकरण को एक अपील या केन्द्रीय सरकार को एक आवेदन किया जाता है। /
In case, if the order covers various numbers of order- in Original, fee for each O.I.O. should be paid in the aforesaid manner, not withstanding the fact that the one appeal to the Appellant Tribunal or the one application to the Central Govt. As the case may be, is filled to avoid scriptoria work if excising Rs. 1 lakh fee of Rs. 100/- for each.
- (E) यथासंशोधित न्यायालय शुल्क अधिनियम, 1975, के अनुसूची-I के अनुसार मूल आदेश एवं स्थगन आदेश की प्रति पर निर्धारित 6.50 रुपये का न्यायालय शुल्क टिकिट लगा होना चाहिए। /
One copy of application or O.I.O. as the case may be, and the order of the adjudicating authority shall bear a court fee stamp of Rs. 6.50 as prescribed under Schedule-I in terms of the Court Fee Act,1975, as amended.
- (F) सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (कार्य विधि) नियमावली, 1982 में वर्णित एवं अन्य संबन्धित मामलों को सम्मिलित करने वाले नियमों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है। /
Attention is also invited to the rules covering these and other related matters contained in the Customs, Excise and Service Appellate Tribunal (Procedure) Rules, 1982.
- (G) उच्च अपीलीय प्राधिकारी को अपील दाखिल करने से संबंधित व्यापक, विस्तृत और नवीनतम प्रावधानों के लिए, अपीलार्थी विभागीय वेबसाइट www.cbec.gov.in को देख सकते हैं। /
For the elaborate, detailed and latest provisions relating to filing of appeal to the higher appellate authority, the appellant may refer to the Departmental website www.cbec.gov.in

ORDER IN APPEAL ::

M/s. Ray Vains Infra Pvt. Ltd., Office No. 24, 4th Floor, Samruddhi Bhavan, Gondal Road, Rajkot (hereinafter referred to as "Appellant") filed present appeal against Order-In-Original No. 67/ST/2016 dated 30.03.2017 (hereinafter referred to as "the impugned order") passed by the Assistant Commissioner, Central Excise Division, Morbi (hereinafter referred to as "the lower adjudicating authority"): -

2. The brief facts of the case are that appellant had provided services of construction of foundation of transformer, cycle stand and repairing of various offices to M/s. Pashchim Gujarat Vij Company Limited (hereinafter referred to as "PGVCL") during FY 2012-13 and FY 2013-14 and services of construction and repairing work of Police Station, construction and repairing of jail building, etc. to M/s. Gujarat State Police Housing Corporation Limited (hereinafter referred to as "GSPHCL") during FY 2013-14 and FY 2014-15, however, no service tax was paid by them. Show Cause Notice No.V.ST/AR-II/ST-RJT/ADC(RKC)/68/2016-17 dated 10.08.2016 (hereinafter referred to as "SCN") was issued to appellant demanding service tax of Rs. 10,04,407/- under proviso to Section 73(1) of the Finance Act, 1994 (hereinafter referred to as "the Act") along with interest under Section 75 of the Act and to impose penalty under Section 76, 77 & 78 of the Act. The lower adjudicating authority vide impugned order confirmed demand of service tax of Rs. 4,52,867/- along with interest and imposed penalty of Rs. 4,52,867/- under Section 78 of the Act with option of reduced penalty and imposed penalty of Rs. 10,000/- under Section 77 of the Act.

3. Being aggrieved with the impugned order, appellant preferred present appeal, *inter-alia*, on the grounds that impugned order is patently against law, contrary to the facts on record, unjust, erroneous and passed without proper justification and application of mind; that the lower adjudicating authority vide Para No. 19.4 mentioned that appellant had failed to provide any documentary evidence to establish that GSPHCL and PGVCL had been set up by an Act of Parliament or State legislature, while at Para No. 12.1 stated that we had provided proof of certificate from the key person of PGVCL and GSPHCL; that they were never under belief that service tax is required to be charged and that they have fully cooperated and disclosed all the fact as and when demanded and produced ST3 returns, Income Tax Returns, Financial Accounts i.e. Balance Sheet and P&L Account, copy of sample invoices, during the course of inquiry, which itself is sufficient to establish their bonafide intention; that exemption under Notification No. 25/2012-ST dated 20.06.2012 and judgment dated 03.03.2016 of Hon'ble High Court of Patna in the case of Shapoorji Paloonji & Company Pvt. Ltd. have not been considered by the lower adjudicating authority; that orders/decisions of various High Courts and CESTAT having same facts of repair and maintenance and of works contracts were not considered; that the lower

adjudicating authority has erred while invoking extended period under proviso to Section 73(1) of the Act; that lower adjudicating authority has erred while ordering to pay interest under Section 75 of the Act and to impose penalty under Section 77 and Section 78 of the Act; that the lower adjudicating authority has not given reasonable opportunity of personal hearing before the case is adjudicated.

4. Personal Hearing in the matter was attended to by Shri Kartik Pandya, Chartered Accountant, who reiterated grounds of appeal and submitted that PGVCL is a Government of Gujarat Company and 99.99% equity is held by Government of Gujarat; that GSPHCL's 100% equity is held by Government of Gujarat; that benefit of Notification No. 25/2012-ST dated 20.06.2012 should be given to them as has been held by Hon'ble High Court of Patna in the case of Shapoorji Paloonji & Company Pvt. Ltd.

FINDINGS: -

5. I have carefully gone through the facts of the case, the impugned order, the appeal memorandum and written as well as oral submissions made during the personal hearing. The issue to be decided is whether the impugned order, in the facts of this case, confirming demand of service tax and imposing penalty is correct or not.

6. It is fact on record that impugned SCN has been issued to appellant under which demand of service tax of Rs. 10,04,507/- for construction services provided to PGVCL and GSPHCL was made for the FY 2012-13 to 2013-14 and for the FY 2013-14 to 2014-15 respectively. The lower adjudicating authority has confirmed demand of service tax in respect of services provided prior to 30.01.2014 and dropped demand of service tax for the period after 30.01.2014 and onwards.

6.1 Appellant has contended that the lower adjudicating authority has not considered exemption from payment of service tax under Notification No. 25/2012-ST dated 20.06.2012, the relevant portion of the said Notification is reproduced as under: -

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 93 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994) (hereinafter referred to as the said Act) and in supersession of notification number 12/2012-Service Tax, dated the 17th March, 2012, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 210(E), dated the 17th March, 2012, the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts the following taxable services from the whole of the service tax leviable thereon under section 66B of the said Act, namely :-

1.;

.....

 12. Services provided to the Government, a local authority or a governmental authority by way of construction, erection, commissioning, installation, completion, fitting out, repair, maintenance, renovation, or alteration of -

(a) a civil structure or any other original works meant predominantly for use other than for commerce, industry, or any other business or profession;

(b) a historical monument, archaeological site or remains of national importance, archaeological excavation, or antiquity specified under the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 (24 of 1958);

(c) a structure meant predominantly for use as (i) an educational, (ii) a clinical, or (iii) an art or cultural establishment;

(d) canal, dam or other irrigation works;

(e) pipeline, conduit or plant for (i) water supply (ii) water treatment, or (iii) sewerage treatment or disposal; or

(f) a residential complex predominantly meant for self-use or the use of their employees or other persons specified in the *Explanation 1* to clause 44 of section 65B of the said Act;

6.2 In view of aforesaid exemption Notification, service provided to Government, Government authority or to local government authority by way of construction and repair & maintenance of civil structures meant predominantly for use other than commerce or industry or any other business or profession is exempted from payment of service tax.

6.3 The term 'Government authority' is defined vide Para 2(s) of the said Notification, which reads as under: -

"governmental authority" means a board, or an authority or any other body established with 90% or more participation by way of equity or control by Government and set up by an Act of the Parliament or a State Legislature to carry out any function entrusted to a municipality under article 243W of the Constitution;

6.4 It can be seen from above that an authority established with 90% or more participation by way of equity or control by Government and set up by an Act of the Parliament or a State Legislature to carry out function under Article 243W of the Constitution is defined as Government authority.

6.5 The term 'Government authority' has been redefined vide Notification No. 2/2014-ST dated 30.01.2014, which reads as under:-

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 93 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 25/2012-Service Tax, dated the 20th June, 2012, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* G.S.R. 467(E), dated the 20th June, 2012, namely :-

In the said notification, in the paragraph 2, for clause(s), the following shall be substituted, namely:-

'(s) "governmental authority" means an authority or a board or any other body;

(i) set up by an Act of Parliament or a State Legislature; or

(ii) established by Government,

with 90% or more participation by way of equity or control, to carry out any function entrusted to a municipality under article 243W of the Constitution;'

6.6 In view of the above, it can be seen that the word "and" existed between sub-clause (i) and sub-clause (ii) of the definition of 'Government Authority' has been substituted by the word "or" vide Notification No. 2/2014-ST dated 30.01.2014, according to which, "Government Authority" means an authority set up by an Act of Parliament or a State Legislature or established by Government with 90% or more participation by way of equity or control to carry out function under Article 243W of the Constitution.

6.7 Appellant has submitted copy of certificates issued by concerned authority specifying that Government of Gujarat is holding 90% or more participation by way of equity or control over PGVCL and GSPHCL. However, the appellant has not submitted any documentary evidence in support that both these companies were set up by an Act of the Parliament or a State Legislature to carry out any function entrusted to a municipality under Article 243W of the Constitution, which is required as per the pre-amended definition of 'Government Authority' prior to 30.01.2014. Hence, I am of the considered view that impugned order passed by the lower adjudicating authority confirming demand of service tax in respect of construction services provided to PGVCL and GSPHCL for the period prior to 30.01.2014 is correct, legal and proper and therefore, I uphold the impugned order.

6.8 Appellant has relied on judgment of Hon'ble High Court of Patna in the case of Shapoorji Paloonji & Company Pvt. Ltd. reported as 2016 (42) STR 681 (Pat.). I find that ratio of the said decision cannot be applied in the present case as department has preferred Civil Appeal before Hon'ble Supreme Court against the said judgment and the matter does not attain finality.

7. As regard to penalty imposed under Section 77 of the Act, I find that appellant failed to assess service tax liability in respect of construction services provided to PGVCL and

GSPHCL and failed to declare taxable value of services in their ST-3 returns filed from time to time, they are liable for penalty under Section 77 of the Act and therefore, I uphold penalty of Rs. 10,000/- imposed upon them under Section 77 of the Act.

8. As regard to penalty imposed under Section 78 of the Act, I find that appellant has declared that they have provided construction service to GSPHCL and PGVCL and not claimed exemption from payment of service tax. The entire transactions came to the knowledge of the department only when inquiry was initiated against them. Hence, I find that ingredient of suppression of facts with intent to evade payment of service tax is present in the instant case. Therefore, I find that lower adjudicating authority has correctly imposed penalty equal to service tax evaded by the appellant in terms of Section 78 of the Act and I uphold the same.

9. In view of above factual and legal position, I uphold the impugned order and reject appeal filed by the appellant.

९.१ अपीलकर्ता द्वारा दर्ज की गई अपील का निपटारा उपरोक्त तरीके से किया जाता है।

9.1. The appeal filed by the Appellant stand disposed off in above terms.

K. Kumar
31/5/18
(कुमार संतोष)
आयुक्त (अपील्स)

K. Kumar
31/5/18
आयुक्त (अपील्स)

By RPAD

To,

1.	M/s. Ray Vains Infra Pvt. Ltd., Office No. 24, 4 th Floor, Samruddhi Bhavan, Gondal Road, Rajkot	मे. रे वाइंस इन्फ्रा प्रा. लिमिटेड, ऑफिस न. २४, चौथी मंज़िल, समृद्धि भवन, गोंडल रोड, राजकोट
----	---	--

Copy for information and necessary action to:

- 1) The Chief Commissioner, GST & Central Excise, Ahmedabad Zone Ahmedabad for his kind information.
- 2) The Commissioner, GST & Central Excise, Rajkot Commissionerate, Rajkot.
- 3) The Assistant Commissioner, GST & Central Excise Division-I, Rajkot.
- 4) Guard File.

